राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के

कोल ब्लॉकों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलना सुनिश्चित

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ प्रदेश मे आवंटित 'पारसा ईस्ट व केंते बेसन' कोल ब्लॉको को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलना सुनिश्चित हो गया है। इन ब्लॉको के लिए प्रथम चरण की वानिकी स्वीकृति इस वर्ष जुलाई माह में प्राप्त हो चुकी है।

ऊर्जामंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की 'एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी' (ई ए सी) ने सोमवार को नागपुर में सम्पन्न बैठक में इन ब्लॉकों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के इस संदर्भ में केन्द्र सरकार के स्तर पर अथक प्रयासो के फलस्वरुप यह स्वीकृति जारी होने जा रही है। ऊर्जामंत्री ने बताया कि स्वयं उन्होंने भी इस विषय में संबंधित मंत्रालयों से निरन्तर सम्पर्क एवं अनुसरण किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पर्यावरण स्वीकृति मिलनेके साथ ही अगले दस–बारह महिनों में इन ब्लॉकों से राज्य की विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला मिलना प्रारम्भ हो जायेगा।

ऊर्जामंत्री ने बताया कि राज्य क्षेत्र में इस समय कालीसिन्ध झालावाड, (2 X 600 मेगावाट) एवं छबडा (2 X 250 मेगावाट) की इकाइयां निर्माणाधीन है और सूरतगढ तथा छबडा में प्रत्येक 660 मेगावाट की 4 सुपर किटिकल थर्मल इकाइयों की स्थापना का कार्य भी हाथ में लिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए कोयले की व्यवस्था इन कोल ब्लॉको से की जानी है जिनकी भंडारण क्षमता लगभग 450 मिलियन टन है।

नागपुर में सम्पन्न ई ए सी की बैठक में ऊर्जा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी.एन.सिंहल, व निदेशक तकनीकी श्री एन.एम.माथुर ने निगम का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य की बिजली परियोजनाओं के हित में इन कोल ब्लॉकों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र जारी करने पर जोर दिया।

––––